



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राप्तिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, मुकवार, जुलाई 13, 1990/अष्टावृ 22, 1912  
No. 284] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1990/ASADHA 22, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह संचालन

श्रद्धिमुच्चना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1990

सा.का.नि. 632 (ग).—दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह शिविल सेवा नियम, 1971 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह शिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 में और संगोष्ठी करने के लिए एन्द्रध्राग निम्नलिखित विनियम बनायी है, अर्थात्—

1 (1) इन विनियमों को दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह शिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण, और विभागीय परीक्षा) संशोधन विनियम, 1990 का जाएगा।

(2) ये विनियमन सरकारी राजगत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह शिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 में—

"(1) विनियम 4(क) में उप-विनियम (1) में निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिष्ठापित बर्ते कि जिस परिवीक्षार्थी ने कुल प्रतिशत 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं किन्तु किसी एक पेपर में 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे परीक्षा में उनीं मात्रा जाएगा बर्ते कि उसने एक पेपर को छोड़कर अस्थि सभी पेपरों में 60 प्रतिशत अथवा उसमें अधिक अंक प्राप्त किए हैं।"

(ग) उप विनियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम जोश जाएगा, अर्थात्—

"जो परिवीक्षार्थी उप-विनियम 3 के छंड (क) में उल्लिखित भाग—I लिखित परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण करता है, को ऐसी विभागीय परीक्षा की प्रतिम तरीख से सेवा के प्रवेश प्रेष (एट्री प्रेष) में दूसरी बैनवूँडी दी जाएगी जिसे अविष्य में होने वाली बैतन-वृद्धि में समाहित कर निया जाएगा।"

ठज्जर्ते कि किसी उरियोजनार्थी को अनुचित वेतन बढ़ित तथा मही दी जाएगी जब तक कि वह उप विनियम (1) के अंतर्गत निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करे;

(2) विनियम 5 में, "विभागीय परीक्षा" शब्दों के पश्चात तथा "अधिकार के द्वारा" शब्दों में पहले आए "उच्चतर स्तर" शब्दों को हटाया जाएगा;

(3) अनुसूची में "दिल्ली, अस्सम और निकोबार दीन समूह सिविल सेवा परिवीक्षणियों को विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम मूली" शब्द के अंतर्गत "नोट" के पश्चात दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए अर्थात् :—

1. मूल आधिक सिद्धांत जिसमें प्रबन्धकीय अवधारणाएं तथा भारत की पञ्चवर्षीय योजनाएं भी शामिल हैं।

तीन घंटे की अवधि का एक वेपर होगा (अधिकतम 200 अंक) वेपर दो भागों में होगा और प्रत्येक भाग के 100 अंक होंगे। भाग (क) मूल आधिक अवधारणाएं तथा भाग (ख) प्रबन्धकीय अवधारणाएं।

भाग (क) मूल आधिक अवधारणाएं—राष्ट्रीय आर—प्रवाहारा और गणन पद्धति; आय के भिन्नान, जनसंख्या बढ़ि; मूल्य नियरिण पूँजी निर्भाण अदि; योजनावाद आधिक विकास-पञ्चवर्षीय योजनाएं तथा पञ्चवर्षीय योजनाओं में व्यपनाएं जैसे बाली विभिन्न योजना नीतियां अर्थव्यवस्था प्रबन्ध के लिए नीति तंत्र; कृषि और कृषि आपारित उत्थोग का विकास; सामीण विकास कार्यक्रम जिसमें आई.आर.डी.पी. एन.प्रार.भी.पी., आर.एल.ई.ई.जी.पी. जैसे किया जाए, अर्थात्—

"प्रत्येक परिवीक्षणीय को परिवीक्षा अधिकार के द्वारा विभागीय परीक्षा पास करना अपेक्षित है।"

(2) विनियम 4(ख) में उप-विनियम (3) से खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

- (1) मूल आधिक सिद्धांत जिसमें प्रबन्धकीय अवधारणाएं और भारत की पञ्चवर्षीय योजनाएं भी शामिल हैं।
- (2) मूल राजनीतिक अवधारणाएं तथा भारत का संविधान।
- (3) भारत में जिला प्रशासन के विशेष संदर्भ सहित लोक प्रशासन की मूल अवधारणाएं।
- (4) मुख्य अधिनियम।
- (5) विषय अधिनियम।
- (6) केन्द्रीय योजना नियम, सामान्य वित्तीय नियम तथा अन्य सेवा नियम।
- (7) भाषा हिन्दी (मानिक भाषा शामिल है)।
- (8) खंड (ग) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रत्येक परिवीक्षणीय को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में त्यन्तम् 60 प्राप्तशत अक प्राप्त करना अपेक्षित है :

कार्यक्रम तथा अनुचित जाति और अनुचित जनजाति विकास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं; औद्योगिक विकास-बड़े तथा मध्यम स्तर के उत्थोग और नव उद्योग; संस्थागत अण-बैंकिंग तथा अन्य संस्थागत विकास; सार्वजनिक सेवा के प्रतिष्ठान।

पांग (ख) —प्रत्यक्षकोष अवधारणाएं—शास्त्र शास्त्र, प्रौद्योगिक वित्त निधि वेतन एवं वी.पी., संघर्ष प्रबन्धक, पर्वतीन वर्गधर्म, कार्यविवरणात्मक विषयेषण, एम.प्राई.एम.—संग ठन एवं पद्धति—प्रीर कार्य अध्ययन—गार्ड/मी.पी.एम., सभ्य 'प्रबन्ध-विषय प्रस्तुत करने की पद्धति—वित्तीय प्रबन्ध, एवं वृक्ष।

I. व्यवस्था, डिस्काउंटिंग बैंग कलो—अनुपांग विषयेषण, परियोजना नियमण, नागल नाम विशेषण, परियोजना मूल्यांकन, त्रुलन-ग्रन्थ एवं व्याप्ता, जीरो-वेस व्याप्तिंग तथा नियामन ग्रन्ट।

### II. मूल राजनीतिक अवधारणाएं तथा भारत का संविधान

तीन घंटे की अवधि का एक वेपर होगा (अधिकतम 100 अंक) वेपर 2 भागों में होगा और प्रत्येक भाग के 50 अंक होंगे। भाग (क) मूल राजनीतिक अवधारणाएं तथा भाग (ख) भारत का संविधान (प्रोजेक्टी भाव्य में)—निम्निति परीक्षा में उपलब्ध कराया जाएगा।

भाग (क) मूल राजनीतिक अवधारणाएं—राजनीतिक विचार-धाराएं तथा अवधारणाएं जिसमें गांधीवादी मिडांग भी शामिल है; भारतीय राजनीतिक पद्धति जिसमें संसदीय लोकतंत्र शामिल है, राजनीतिक गठन के विभिन्न प्रभावी दलों का मूल्यांकन और उनकी भूमिका; अणांति-विचारी, काण्डकार जातियां, साम्प्रदायिक और प्रोजेक्टी उमका स्वभाव तथा समाज पर उनका प्रभाव; नागरिक उमके अधिकार तथा राज्य और प्रभुमता मौजूदा पर्यावरण में काल्याणकारी गत्य का आधार, मूल्यांकन तथा अंतर्गतीय संगठनों विषयेषकर संयुक्त गढ़ संघ की भूमिका।

भाग (ख) भारत का संविधान : इसका मूल्यांकन जिसमें संसंघता संयम का इतिहास; सौक्रिय अधिकार और कर्मश; राज्य की नीति के नीति निर्देशक मिशन, संसदीय पक्षिय तथा पद्धति; केन्द्र और राज्य संघेश; संकटकालीन प्रावधान संणेश्वन—अनुष्टुप्त 370 तथा 371 के प्रत्यान विशेष प्रावधान; अन्यमैक्षकों की भूरस्ता,

### III. भारत में जिला प्रशासन के विशेष संदर्भ में लोक प्रशासन को मूल अवधारणाएं

इसमें अधिकतम 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि तीन घंटे होंगी। प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे। भाग (क) लोक प्रशासन तथा भाग (ख) भारत में जिला प्रशासन। प्रत्येक भाग के अस्तर्गत निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :—

#### भाग (क) लोक प्रशासन :—

- (i) लोक प्रशासन का सार—सरकारों की संगठनात्मक संरचना;
- (ii) सिविल सेवकों की भूमिका;
- (iii) प्रशासनिक आचार-शास्त्र तथा उत्तरदायित्व;
- (iv) प्रत्यायोजना तथा विकेन्द्रीकरण—जिला तथा स्वानीय प्रशासन;
- (v) कार्यक्रम प्रशासन-पुलिस-प्रशासन—जैल प्रशासन—पंचायत राज्य प्रशासन;
- (vi) आपदा प्रशासन—विकास तथा कल्याण कार्यक्रमों का प्रशासन;
- (vii) बजट तथा लेखा-परीक्षा की भूमिका;
- (viii) जिला प्रधिकारी/अनुमडल प्रधिकारी की भूमिका—जूनांडों का आयोजन; तथा
- (ix) जूनांडों का आयोजन—कानूनी उत्तर्ध।

#### भाग (ख) भारत में जिला प्रशासन :

- (i) सहकारिता—सहकारिता आदोलन तथा इसके कार्यक्रमों का मूल्यांकन;

(ii) सामुदायिक विकास—सामुदायिक विकास की आवधारणा—विषय अस्तु यहां यथा ऐटडे तथा बार्डर्स ने राजनीतिक विषयों में लक्ष्यान्वयन।

(iii) ग्राम, प्रश्नों तथा जिला स्तर की पंचायती राज मंस्थाएँ सम्पादन तथा उनको सौंपे गए कार्य—कार्यालयों की गमन्याएँ; कलेक्टर की भूमिका;

(iv) नगरपालिका प्रशासन—गठन—कार्यालयक कल्य-राजस्व के स्रोत—नियंत्रण तथा पर्योगश—सामान्य प्रशासन—विधायी तथा कार्यालयक विषय से जीव मंस्था;

(v) विधि और अवधारणा को बताए रखना—मैजिस्ट्रेसी तथा पुलिस का धारित्व—कानूनी उपबंध—बल प्रयोग—अमैनिक अधिकारियों के सहायक के रूप में सेवा।

(vi) भूमि अधिग्रहण—प्रक्रिया—भूमावजे का निर्धारण;

(vii) निरीक्षण कार्य—निरीक्षण कार्यों की आवश्यकता—समीक्षा के उद्देश्य—रिपोर्ट जैसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण—निरीक्षण कार्य की प्रक्रिया और अनुगामन कोष निरीक्षण आकस्मिक निरीक्षण;

(viii) चुनाव;

(ix) भूमि सुधार एवं बंदोबस्तु कार्य;

(x) ग्रामीण विधाया;

#### IV. मृद्यु अधिनियम (पुस्तकों महित)

प्रत्येक के लिए अधिकतम 100 अंक और वो घटे की प्रवधि वाले वो प्रश्नालय होंगे, अधिकारियों से उनको दिए जाने वाले मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिखने का अनुरोध किया जा सकता है। प्रश्न के संगत उपबंध के संबंध में अधिकारी से कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। मृद्यु अधिनियम निम्नलिखित है:—

#### प्रश्न पत्र-I.

- भारतीय वड संहिता, 1860
- अपग्रेड प्रक्रिया संहिता, 1973
- भारतीय साम्य अधिनियम, 1872
- सामान्य धाराएं, अधिनियम, 1897
- परिसीमन अधिनियम, 1963

#### प्रश्न पत्र-II

- भारतीय प्रक्रिया संहिता, 1988
- मोटर वाहन अधिनियम, 1989 तथा उसके तहत बताए गए नियम।
- भारतीय अनुवंश अधिनियम, 1872
- आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम तथा उसके नियम।
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894
- स्थायालय शुल्क अधिनियम, 1870

#### I. विधिव अधिनियम (पुस्तकों महित):

वो परीक्षा पत्र होंगे जो अधिकतम 100 अंकों के होंगे जिसकी अवधि दो घटे होगी। अधिकारियों से मामले के तथ्यों के आधार पर, जो कि अधिकारी को सप्लाई किए जाएंगे, निर्णय लिखने का अनुरोध किया जा सकता है। अधिकारी को समस्या से संबंध प्रावश्यों के संबंध सहित उत्तर देने में कुछ कठिनाइयों का मामला भी करना पड़ सकता है। कुछ विधिव अधिनियम निम्न प्रकार है:—

#### परीक्षा पत्र-I.

- ग्राम अधिनियम, 1958 योंग नियम
- दिल्ली पुलिम अधिनियम, 1978
- दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, 1954
- दिल्ली भूमि मुद्रार अधिनियम, 1954
- दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 और नियम
- दिल्ली जोत (मूँछड़ निरोधक एवं धर्मवंदी) नियम, 1959
- दिल्ली पर लाग अनुयार नीपरा पंजाब जोत अधिनियम, 1948
- नागरिक अधिकार अधिनियम, 1972 का संरक्षण
- पंजाब अधिनियम
- अनैतिक यानायान अधिनियम का अधिकरण
- दिल्ली जेत वंहिता

#### परीक्षा पत्र-II

- फैक्टरी प्रविनियम, 1948
- दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975
- रोजगार कार्यालय की रिहित अधिनियम, 1959 की अविवार्य अधिसूचना।
- आवश्यक बस्तु अधिनियम।
- धर्मों में लागू विधियां धम जात जैसे आद्योपिक विद्याव अधिनियम, दुकान एवं पंथा अधिनियम, अप्रिक अनुदूति अधिनियम, यन्त्रतम मञ्चरूरी अधिनियम, देढ़ यनियन एप्ट, 1926 द्वारा।
- पंजाब आवकारी अधिनियम, 1914
- यू. पी. एन्टरटेनमेंट एड बेटिंग एप्ट, 1937 जैसे कि सभ शामित छेत्र दिल्ली में किया गया है।
- खाद्य वस्तुओं में मिलानट निरोधक अधिनियम, 1954
- दिल्ली महकारी समितियां अधिनियम
- दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966

#### VII. केन्द्रीय कोषागार नियम भारतीय विधि नियम तथा भव्य भेदा नियम (पुस्तकों सहित)

अधिकतम 100 अंकों का एक परीक्षा पत्र होगा जिसकी अवधि दो घटे होगी। अधिकारियों से समस्या से संगत नियमों के आधार पर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है।

- केन्द्रीय कोषागार नियम, मानविकी वित्त नियम और अव्य सेवा नियम।
- केन्द्रीय कोषागार नियम बोल्डम I और II
- सिविल सेवा विनियम बोल्डम I और II
- मौसिक नियम और प्रतिपूरक नियम, बोल्डम I और II
- सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960
- वित्तीय मण्डिन प्रत्यायोजन नियम, 1978
- के. बी. सेवा आवरण नियमाधली, 1965
- सी.सी.ए. नियम, 1965
- सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी बोल्डर।

10. प्राप्तिकार विवेदिका समितियम्, 1947 के उपबंधों के गाँव पठिन भर्तीकारा समिति बोल्डपृष्ठ 1 भाग II
11. संगठन तथा परिवर्ति प्रक्रिया।
12. सरकारी लेखा परीक्षा और लेखा का परिवर्त्य।

**भाषा:**

हिन्दी: एक परीक्षा पत्र होगा जिसको शब्दियि 2 घंटे होगी और प्रधिरात्रम् 75 अंकों का होगा। एक मौखिक टेस्ट 25 अंकों का होगा।

**(क) लिखित:**

- (i) अंग्रेजी पैरे का हिन्दी में अनुवाद
- (ii) हिन्दी पैरे का अंग्रेजी में अनुवाद
- (iii) विशिष्ट विषयों में से एक पर हिन्दी में प्रस्ताव।

**(ख) मौखिक:**

भाषा को धारा प्रवाह रूप से बोलने और पढ़ने में परिवीकाशीन प्रधिकारी की योग्यता को जानने के लिए मौखिक परीक्षा की जाती है।

[स. 14012/12/89-ग. टी.एस.]  
प्रकाश चन्द्र, निवेशक (सी.पी.एस.)

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 1990

G.S.R. 632(E).—In pursuance of rule 32 of the Delhi Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following regulations, further to amend the Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Probation, Training and Departmental Examination) Regulations, 1972, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Probation, Training and Departmental Examination) Amendment Regulations, 1990.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service (Probation, Training and Departmental Examination) Regulations 1972—

- (1) in regulation 4(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

“Every probationer shall be required to pass departmental examination during the period of probation.”;

- (2) in regulation 4(b) in sub-regulation (3) after clause (a), the following clauses shall be substituted namely :—

1. Basic Economic Principles including Management Concepts and Five Year Plans of India.

8. Basic Political Concepts and the Constitution of India.

3. Basic concepts of Public Administration with particular reference to District Administration in India.

4. Major Acts.

5. Miscellaneous Acts.

6. Central Treasury Rules, General Financial Rules and other Service Rules.

7. Language—Hindi (including oral);

B. for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) Every probationer shall be required to obtain a minimum of 60 per cent marks in each subject to pass therein :

Provided that a probationer who has obtained 60 per cent marks in aggregate but has secured 50 per cent or more marks in one paper, shall be deemed to have qualified the examination, if in all papers except the one, he has secured 60 per cent or more marks.”;

C. After sub-regulation (8), the following sub-regulations shall be inserted namely :—

“(a) The probationer who passes the Part I Written Examination as mentioned in clause (a) of sub-regulation 3 in the first attempt, shall be allowed second increment in the entry grade of service absorbable in future increases of Pay, from the last date of such departmental examination :

Provided that a probationer shall not be allowed to draw subsequent increment unless he qualifies the departmental examination as prescribed under sub-regulation (1).”;

(2) In regulation 5, the words “by the higher standard” appearing after the words “departmental examination” and before “during the period” shall be omitted;

(3) In the Schedule, under the heading “Syllabus for departmental examination of the Delhi, Andaman and Nicobar Islands Civil Service Probationers,” for the entries after ‘Note’ the following entries shall be substituted, namely :—

I. Basic Economic Principles including Management Concepts and Five Year Plans of India.

There shall be one paper (Maximum marks 200) of three hours duration. Paper will have two parts, each part having 100 marks. Part (a) Basic Economic Concepts and part (b) Management Concepts.

Part (a)—Basic Economic Concepts · National Income—Concept and method of calculation; Laws of returns; Population Growth· Pricing, Capital formation etc.; Planned Economic Development—Five Year Plans and various Planning Strategies followed in Five Year Plans; Policy Instrument for Managing the Economy; Development of Agriculture and Agro-based Industries; Rural Development Programmes including Programmes like IRDP, NRD, RLEEGP

and Programmes for the Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Industrial Development—Large and Medium Scale Industries & Small Scale Industries; Institutional Credit—Development of Banking and other Institutional Finance; Public Sector Undertakings.

**Part (b)**—Management Concepts.—Behavioural Science, Motivation, Leadership, decision-making, MBO, Management of Conflicts, Management of change, Transactional Analysis, MIS-O and M and Work Study—Part CPM, Time-Management—Methodology of Presentation of a subject—Financial Management, Capital Budgeting, Discounted Cash Flow, Ratio-Analysis, Project Formulation, Cost-Benefit Analysis, Project Evaluation, Interpretation of Balance Sheets, Zero-base Budgeting and Performance Budgeting.

## II. Basic Political Concepts and the Constitution of India :

There shall be one paper (maximum marks 100) of three hours duration. Paper will have two parts, each part having 50 marks. Part (A) Basic Political Concepts and Part (B) Constitution of India (in English edition) will be provided at the written examination.

**Part (A) Basic Political Concepts.**—Political Ideologies and Concepts including Gandhian Ideology, Indian Political Systems including Parliamentary Democracy; Evolution and role of various Pressure Groups in a political set up; Unrest—students, Agrarian Castes, communal and Industrial—their nature and impact on Society; A citizen—his rights and the State and Sovereignty—Meaning of a Welfare State in present environment, evolution and role of International organisations particularly the UNO.

**Part (B) Constitution of India.**—Its evolution including history of freedom struggle; Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of the State Policy; Parliamentary Procedures and Practices; Centre and State Relations; Emergency Provisions; Amendments—Special Provisions under Article 370 and 371; Safeguards for Minorities; services under the Union and the States; voting behaviour in India and present political scene.

**III. Basic Concepts of Public Administration with particular reference to District Administration in India**—There shall be one paper (maximum marks 100) of three hours duration. Paper will have two parts. Part (A) Public Administration and Part (b) District Administration in India. Each part will cover the following subjects :—

## Part (A) Public Administration :

- (i) Essentials of Public Administration—Organisational structure of Governments;
- (ii) Role of Civil Servants;
- (iii) Administrative Ethics and Accountability;
- (iv) Delegation and Decentralisation.—District and Local Administration;
- (v) Personnel Administration.—Police Administration—Jail Administration—Panchayat Raj Administration.

- (vi) Calamity Administration—Administration of Development and Welfare Programmes;
- (vii) Budget and Role of Audit
- (viii) Role of District Officer/SDO—Conduct of Elections and;
- (ix) Conduct of Elections—Legal provisions.

## Part (B) District Administration in India :

- (i) Co-operatives—Co-operative Movement and appraisal of its programmes,
- (ii) Community Development—The concept of community Development—the content organisation pattern and implementation of Programme—performance appraisal.
- (iii) Panchayat Raj Institutions at the village, block and district levels—resources and functions assigned—problems in implementation—role of Collector;
- (iv) Municipal Administration—Constitution—the executive functions—sources of revenue—control and supervision—general administration—relationship between deliberative and executive wings;
- (v) Maintenance of law and order—the responsibilities of the Magistracy the police—legal provisions—use of force—the army as an aid to civil authorities.
- (vi) Land acquisition—Procedure—determination of compensation;
- (vii) Inspections—need for inspections—objectives of review—report viz. inspections by personal visits—procedure for inspections and compliance field inspections surprise inspections.
- (viii) Elections.
- (ix) Land reforms & Settlement operations.
- (x) Rural development.

## IV Major Acts (with books):

There shall be two papers each having maximum 100 marks and of two hours duration. The officers can be requested to write the judgment on the basis of facts of the case which will be supplied to the officer. Some problems can also be posed to the officer for answer with reference to the provision relevant to the problem. Major Acts are :—

### Paper I:

1. The Indian Penal Code, 1860.
2. The Code of Criminal Procedure, 1973.
3. The Indian Evidence Act, 1872.
4. The General Clauses Act, 1897.
5. The Limitation Act, 1963.

### Paper II :

1. The Code of Civil Procedure, 1908

2. The Motor Vehicle Act, 1989 and the rules framed there under.
3. The Indian Contract Act, 1872.
4. The Maintenance of Essential Services Act and the Rules thereunder.
5. The Land Acquisition Act, 1894
6. The Court Fee Act, 1870.

V. Miscellaneous Acts (with books) :

There shall be two papers each having maximum 100 marks and of two hours duration. The officers can be requested to write the judgment on the basis of facts of the case which will be supplied to the officer. Some problems can also be posed to the officer for answer with reference to the provisions relevant to the problem. Miscellaneous Acts are—

Paper I :

1. The Arms Act, 1958 and the rules.
2. The Delhi Police Act, 1978.
3. The Delhi Panchayat Raj Act, 1954.
4. The Delhi Land Reforms Act, 1954.
5. The Delhi Land Revenue Act, 1954 and the rules.
6. The Delhi Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1959.
7. Third Punjab Holding Act, 1948 as applicable to Delhi.
8. Protection of Civil Rights Act, 1972.
9. Dowry Prohibition Act.
10. Suppression of Immoral Traffic Act.
11. The Delhi Jail Manual.

Paper II :

1. The Factories Act, 1948.
2. The Delhi Sales Tax Act, 1975.
3. Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act, 1959.
4. The Essential Commodities Act.
5. Various Labour Laws as applicable in the Territory like Industrial Disputes Act, Shops and Establishments Act, Workman Compensation Act, Minimum Wages Act, Trade Union Act, 1926, etc.
6. Punjab Excise Act, 1914.
7. U.P. Entertainment and Betting Act, 1937 as extended to U.T. Delhi.
8. Prevention of Food Adulteration Act, 1954.

9. The Delhi Co-operative Societies Act & the rule.

10. Delhi Administration Act, 1966.

VI. Central Treasury Rules, G.F. Rs. & other Service Rules (with books except Sl. No. 10 to 12).

One paper of 2 hours duration and 100 maximum marks. Officers are expected to provide answers to the problems with reference to the rules relevant to the problem posed.

1. Central Treasury Rules, General Financial Rules and other Service Rules.
2. Central Treasury Rules, Volume I & II.
3. Civil Service Regulations, Volume I & II.
4. Fundamental Rules and Supplementary Rules, Vol. I & II.
5. General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.
6. Delegation of Financial Power Rules, 1978.
7. CCS Conduct Rules, 1965.
8. CCA Rules, 1965.
9. Broucher on Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services.
10. Vigilance Manual Vol. I & II read with Provisions of Prevention of Corruption Act, 1947.
11. O & M Procedure.
12. Introduction to Govt. Audit & Accounts.

VII Language :

Hindi : There shall be one paper of 2 hours duration having 75 marks. There shall also be an oral test of 25 marks.

(a) Written :

- (i) Translation of an English passage into Hindi.
- (ii) Translation of a Hindi passage into English.
- (iii) An essay in Hindi on one of the specified subjects.

(b) Oral :

Oral test is intended to test the ability of the probationer to speak and to read the language fluently.

[No. 14012 12/88-UTS]

PARKASH CHANDER, Director (CPS)